यूपी औद्योगिक विकास के शीर्ष की ओर

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) ने बजट को विकासशील और यूपी को देश में औद्योगिक दृष्टि से शीर्ष पर पहुंचने की राह पर अग्रसर करार दिया। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल ने कहाकि जिस प्रकार से बजट में सड़क निर्माण, आवास एवं शहरी नियोजन, ग्राम्य विकास, हवाई अड्डों के विकास, ऊर्जा एवं नगर विकास हेतु बजट में प्रावधान किये गये हैं। उससे प्रदेश के सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को अप्रत्यक्ष लाभ अवश्य होगा।

सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन की घोषणा का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। उन्होंने कहा कि जिन भी नये औद्योगिक क्षेत्रों का विकास सरकार कर रही है। उसमें सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को भूमि के आवंटन में पारदर्शिता बरती जानी चाहिए, जिससे भ्रष्ट अधिकारी

05 वर्षों में 22 सौ मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य

03 सौ करोड़ रुपये का प्रावधान खाद्य प्रसंस्करण के लिए

प्रक्रिया क ी खामियों का दुरुपयोग न कर सकें।

एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश गोयल ने कहा कि जिस प्रकार से सरकार ने सड़कों के विकास एवं रखरखाव पर लगभग 14 हजार करोड़ रुपये और हवाई अड्डों पर लगभग 400 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है। इससे आवागमन सुगम होगा। एसोसिएशन के महासचिव आलोक अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार के सौर ऊर्जा के विकास के लिए प्रयास जिसके अन्तर्गत 22000 मेगावाट का लक्ष्य आगामी 05 वर्षों के लिए रखा गया है। बजट में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहन के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। परन्तु कृषि प्रधान देश के इस सबसे बड़े राज्य में यह प्रावधान कम से कम 1000 करोड़ रुपये करने की आवश्यकता है, जिससे प्रदेश में न केवल औद्योगिक विकास होगा। आईआईए के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अवधेश अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के शहरों में जाम की स्थिति को देखते हुए यद्यपि मेट्रो रेल का विकास किया जा रहा है। परन्तु इसमें और गति लाने की आवश्यकता है।

युवा, महिलाओं और किसानों पर फोकस

लखनऊ। सीआईआई (कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) यूपी स्टेट काउंसिल ने कहा कि वित्तमंत्री ने समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए किसान, युवाओं और महिला कल्याणकारी बजट पेश किया है। यूपी स्टेट काउंसिल के चेयरमैन आकाश गोयनका ने बताया कि गंगा एक्सप्रेस-वे और आगरा मेट्रो सहित प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन का आवंटन, उत्तर प्रदेश के लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर सरकार के रणनीतिक जोर को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह प्राथमिकता समग्र कनेक्टिविटी को बढ़ाने और क्षेत्र में आर्थिक विकास सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। सेमीकंडक्टर नीति की मंजूरी सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना और विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।